सांध्य दैनिक

4PM

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 8 ● अंक: 203 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2022

मीठे वचन सब ओर सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक मन्त्र होते हैं इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करें।

-तुलसीदास

इस्तीफा देने की जगह फिर विश्वास... 7 | लोक सभा चुनाव: प्रदेश में विपक्ष... 3 | अखिलेश पहले परिवार में सद्भाव... 2

और बढ़ी नौसेना की ताकत, पीएम ने सौंपा आईएनएस विक्रांत

» गुलामी के प्रतीक से मिली नौसेना को मुक्ति, ध्वज को बदला गया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि में नौसेना को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत सौंपा। इस पोत के शामिल होने से नौसेना की ताकत दोगुनी हो गई है। इस मौके पर पीएम ने गुलामी के प्रतीक वाले नौसेना के ध्वज को बदलकर नए ध्वज का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है, जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। अगर समंदर और चुनौतियां अनंत हैं तो भारत का उत्तर है, विक्रांत।

उन्होंने कहा कि पिछले समय में इंडो-पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरंदाज किया जाता रहा लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक, हर दिशा में काम कर रहे हैं। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित, नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। गौरतलब है कि विक्रांत दुश्मनों के लिए बेहद घातक है। इस पर मिग 29के लड़ाकू विमान और 10 Kmaov हेलिकॉप्टर के दो स्क्वॉड्रन तैनात हो सकते हैं। इस युद्धपोत पर 35 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं।

यह हुआ बदलाव

देश के आजाद होने के बाद भारतीय सेना में ब्रिटिश औपनिवेशक झंडे और बैज का ही इस्तेमाल होता रहा। 26 जनवरी 1950 को ध्वज के पैटर्न में सिर्फ भारतीयकृत बदलाव किये गये थे। ध्वज में यूनियन जैक को तिरंगे से बदल दिया गया था लेकिन जार्ज क्रास को छोड़ दिया गया था। अब इसको बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जिस नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया है उसमें झंडे के ऊपरी बाएं कोने में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर दाएं ओर मध्य में नौसैनिक क्रेस्ट को स्थान दिया गया है।

मोदी के बयान पर नीतीश का पलटवार, कहा

वे क्या बोलते हैं ध्यान नहीं देता, कोई नहीं बचा रहा भ्रष्टाचारियों को

» झारखंड-दिल्ली में भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर भी कसा तंज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वे क्या बोलते हैं, मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूं। बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा है।

नीतीश कुमार ने कहा, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सभी लोगों का ख्याल रखा। यहां बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। आपने देखा होगा कितना काम हुआ है। कोई केंद्र में क्या बोलता है, इस पर हम ध्यान नहीं देते।

भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले आरोप पर नीतीश कुमार ने कहा, कहां भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए। वे क्या बोलते हैं, अपना बोलें, हमसे कोई मतलब नहीं। बिहार में भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इधर-उधर के राज्यों में जो लाने-ले जाने का काम हो रहा है, उसे लेकर पीएम मोदी को सोचना चाहिए। नीतीश का इशारा झारखंड-दिल्ली में भाजपा पर लगे रहे विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों को लेकर था। दरअसल, पीएम मोदी ने गुरुवार को केरल में कहा था कि कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए एक गुट में संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने इशारों में लालू यादव को लेकर नीतीश पर निशाना साधा था। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था।

बिहार में भ्रष्टाचारियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, लगातार कर रहे हैं काम

मिशन-2024 पर निकलेंगे नीतीश, राज्यों का करेंगे दौरा

पटना। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन-2024 की शुरुआत कर दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद अब खबर आ रही है कि नीतीश मिशन-2024 के लिए खुद को लॉन्च करने के लिए अगले सप्ताह दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मुख्यमंत्री अगले सप्ताह बिहार से बाहर जाकर इस मिशन को धार देंगे। वे हरियाणा, राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों में जाने की योजना बनाएंगे। गौरतलब है कि जेडीयू दफ्तर में नीतीश कुमार की तस्वीर और आगाज हुआ, बदला होगा, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा जैसे नारों के साथ बैनर लगे हुए हैं।

जनसंख्या नियंत्रण की याचिका पर केंद्र को 'सुप्रीम' नोटिस

» केंद्र को कारगर गाइडलाइन जारी करने के आदेश देने की उठायी मांग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज जनसंख्या नियंत्रण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कारगर गाइडलाइन जारी करने व उचित नियम बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस केएम जोसफ और ऋषिकेश राय की एक बेंच ने सरकार से प्रतिक्रिया मांगी। साथ ही मामले को इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया।

अखिल भारतीय संत समिति के जनरल सेक्रेटरी, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और इसलिए समस्याएं आ रहीं हैं। गरीबी बढ़ गई है। खाने की सप्लाई और स्वास्थ्य सुविधाओं के सीमित होने से मुश्किलें भी लाजिमी हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि केंद्र सरकार को इसके लिए कारगर और प्रभावी नियम कानून व उचित गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए जाएं ताकि देश के लाखों लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। इसके अलावा महीने के पहले रविवार को हेल्थ संडे घोषित करने की मांग की गई है।

कश्मीरी पंडितों के नरसंहार मामले पर सरकार के पास जाने की सलाह

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के मामले पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता एनजीओ वी द सिटीजंस को केंद्र सरकार के समक्ष रिप्रेजेंटेशन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ से कहा कि पहले आप सरकार के पास जाएं। वहां रिप्रेजेंटेशन दें, फिलहाल अपनी याचिका वापस लें। याचिका में तीन दशक पहले हुई घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर जांच कराने, पुनर्वास और संपत्ति वापस दिलाने कि मांग की गई थी। जस्टिस बीआर गवई और सीटी रविकुमार की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कश्मीर में हुए हिंदुओं के उत्पीड़न और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग भी की गई थी।

अखिलेश पहले परिवार में सद्भाव बनाएं, फिर प्रदेश की बात करें : भूपेंद्र सिंह

» बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का सपा प्रमुख पर तीखा हमला

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भाजपा से सामाजिक सद्भाव को खतरा बताने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो अपने परिवार में सामाजिक सद्भाव नहीं बना पाया, वह प्रदेश में सद्भाव की बात कर रहा है। अखिलेश को सलाह दी कि पहले अपने परिवार में सद्भाव बनाएं फिर प्रदेश की बात करें।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को रह-रह कर सपा सरकार का जंगलराज याद आता है, इसीलिए वह बार-बार प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते रहते हैं, जबकि सपा सरकार के दौरान आम आदमी थानों में तो महिलाएं और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े प्रदेश में कानून

व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर आए सुधारों की गवाही दे रहे हैं। यह आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि प्रदेश ने कानून व्यवस्था के मामले में उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूपी माडल को दूसरे राज्य अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में प्रदेश में रोजाना दंगे होते थे, जबकि अब प्रदेश दंगामुक्त हो चुका है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। इतना ही नहीं, प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो चुका है और माफिया पर सरकार पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहले दिन से प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है और भविष्य में भी अपनाई जाएगी। अपराधी छोटा हो या बड़ा, कानून के हिसाब से बिना भेदभाव के कार्रवाई जारी रहेगी। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में आपराधिक घटनाओं को सही तरीके से दर्ज नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में महिला अपराध में यूपी नंबर वन है। एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में जंगलराज साफ दिखाई पड़ता है। बावजूद इसके भाजपा को आधी-अधूरी रिपोर्ट का ढोल पीटने में संकोच नहीं है।

मदरसों में शिक्षा व्यवस्था सुधारेगी सरकार : धर्मपाल

» यूपी बोर्ड की तर्ज पर मदरसों में लागू होंगे बेसिक व माध्यमिक के नियम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसा शिक्षा में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के नियम लागू होंगे। उन्होंने मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि जिस प्रकार यूपी बोर्ड में हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए उम्र की सीमा निर्धारित है, उसी प्रकार मदरसा बोर्ड में भी उम्र की सीमा का अनुपालन कराया जाए।

मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों से मदरसों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के प्रदर्शन का गहन परीक्षण कराया जाए, ताकि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार कर बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। मदरसों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जाए। उन्होंने मान्यता प्राप्त मदरसों में गत वर्षों के छात्रों की संख्या और उन वर्षों में छात्रों को वितरित की गई छात्रवृत्ति का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थानांतरण मदरसा प्रबंधकों की परस्पर सहमति एवं रजिस्ट्रार के अनुमोदन से ही किया जाए।

राजभवन ने सात साल बाद लौटाया राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक

» 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

देहरादून। राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को सात साल बाद राजभवन ने सरकार को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को लौटाने या इसे स्वीकृति देने का अनुरोध राजभवन से किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाएगा। सरकार विधेयक में खामियों को दूर करेगी।

नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। 2015 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2015 में विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा था। तब से

अभी तक इस विधेयक को राजभवन की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। यद्यपि राजभवन ने हाईकोर्ट के निर्णय को देखते हुए विधेयक के विधिक पक्ष को लेकर विधि विशेषज्ञों से परामर्श भी किया था। वर्ष 2004 में एनडी तिवारी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शासनादेश जारी किया था। इस आदेश के आधार पर आंदोलनकारियों को सरकारी विभागों में नौकरी भी मिली थी। इसी वर्ष बीते अप्रैल माह में सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण देने की पैरवी की थी। हाईकोर्ट ने यह प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार कर दिया था।

सपा और रालोद मिलकर लड़ेंगे नगर निकाय चुनाव

» असमंजस की स्थिति को दोनों ने मिलकर किया दूर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मेरठ। सपा व राष्ट्रीय लोकदल जिस तरह से विधानसभा चुनाव -2022 गठबंधन में लड़े थे उसी तरह से नगर निकाय चुनाव भी साथ लड़ेंगे। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष के बयान से तीन दिन तक भ्रम रहने व गठबंधन में असमंजस की स्थिति पैदा होने के बाद गुरुवार को पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया गया है। रालोद के प्रदेश मीडिया संयोजक व पार्टी की तरफ से नगर निकाय चुनाव के लिए गठित पर्यवेक्षकों की टीम के सदस्य सुनील रोहटा ने विज्ञप्ति जारी करके यह स्पष्ट किया है कि नगर निकाय चुनाव सपा व रालोद मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में बयान दिया था जिसको लेकर दोनों पार्टियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब वह पार्टी की तरफ स्पष्ट कर रहे हैं कि दोनों दल साथ हैं और साथ ही चुनाव लड़ेंगे। रालोद की पंद्रह पर्यवेक्षकों की टीम भले ही प्रत्याशी चयन एवं अन्य चुनावी रणनीति को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। लेकिन समय आने पर साझी रणनीति की घोषणा होगी।

मनरेगा में वाट्सएप ग्रुप से जोड़ रहे हैं जनप्रतिनिधियों को : केशव मौर्य

» सरकार मनरेगा में विपक्ष को भी दे रही ताकत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। आमतौर पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में आमने-सामने होते हैं। ऐसे ज्यादातर जनप्रतिनिधि अलग क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। मनरेगा योजना के जरिए अब नए दौर की राजनीति हो रही है, जहां एक ही क्षेत्र के जीते व हारे जनप्रतिनिधि को एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक के प्रतिनिधि वाट्सएप ग्रुप पर जोड़े जा रहे हैं।

इस कदम से सत्तापक्ष का विस्तार होने के साथ ही विपक्ष को भी ताकत मिलेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना की निगरानी पर केंद्र सरकार का विशेष जोर है। लोगों को गांवों में ही रोजगार देने व भुगतान करने में अक्सर खेल होने की शिकायतें मिलती रही हैं। मनरेगा योजना में तकनीक का सहारा लेकर मोबाइल से मानीटरिंग की जा रही है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में वाट्सएप

ग्रुप बन रहे हैं। उसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर सांसद तक के प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा है, ताकि विकास कार्यों का हर दिन आडिट हो सके। खास बात यह है कि हर स्तर पर चुनाव हारने वाले नेताओं को भी ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 58189 ग्राम पंचायतें हैं, सभी गांवों के वाट्सएप ग्रुप में सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ सकते इसलिए उनके प्रतिनिधियों को जोड़ने के निर्देश हैं। गांव के पंचायत सचिव और रोजगार सेवक वाट्सएप ग्रुप बना रहे। गांव में मनरेगा योजना के माध्यम से चल रहे कार्य, मस्टररोल, कितने मजदूर कार्य कर रहे आदि ग्रुप पर साझा किया जाएगा। उस पर मौजूदा जनप्रतिनिधि के साथ विपक्ष के प्रतिनिधि भी निगाह रख सकेंगे।

बामुलाहिजा
कार्टून: हसन जैदी

प्रमुख सचिव गृह के मातहत हो गए उनसे वरिष्ठ सात अफसर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही में हुए फेरबदल के बाद फील्ड में तैनात सात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रमुख सचिव गृह बनाए गए संजय प्रसाद के मातहत हो गए हैं। फील्ड में तैनात पांच जोन के एडीजी और दो शहरों के पुलिस आयुक्त संजय प्रसाद से सीनियर हैं। संजय 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। फील्ड में तैनात आठ जोन में से पांच के एडीजी और चार पुलिस कमिश्नरेट के पदों में से दो पर प्रमुख सचिव से सीनियर आईपीएस अधिकारी तैनात हैं। संजय और डीजीपी के बैच में सात वर्ष का अंतर है।

डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनके अलावा एडीजी कानून व्यवस्था 1990 बैच के हैं। जोन में तैनात अधिकारियों में आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण 1991 बैच, लखनऊ जोन के एडीजी ब्रज भूषण 1992 बैच, मेरठ के एडीजी राजीव सब्बरवाल, प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश 1993 बैच और गोरखपुर के एडीजी अखिल कुमार 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कानपुर के पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड 1991 बैच और लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर 1993 बैच के हैं। वाराणसी के एडीजी जोन रामकुमार, बरेली के एडीजी जोन राज कुमार व नोएडा के पुलिस आयुक्त आलोक सिंह 1995 के अधिकारी हैं। ये संजय के समकक्ष हैं।

लोक सभा चुनाव : प्रदेश में विपक्ष के सफाए को भाजपा ने ठोंकी ताल, माइक्रो प्लान तैयार

» यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत के लिए बनायी गयी रणनीति

» कमजोर बूथों को मजबूत करने पर दिग्गजों का फोकस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में लौटी भाजपा अब लोक सभा चुनाव में जोर-शोर से जुट गयी है। प्रदेश की सभी अस्सी सीटों पर जीत दर्ज करने और विपक्ष के सफाए के लिए पार्टी नेतृत्व ने चुनावी रणनीति का माइक्रो प्लान तैयार किया है। इस प्लान के केंद्र में बूथ हैं। भाजपा का लक्ष्य यह है कि इस बार 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जाए। उस समय भाजपा ने अस्सी में 73 सीटों पर कब्जा किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद कि लोक सभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी, प्रदेश नेतृत्व ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी हर मंच से इस दावे को दोहराते हैं और अब प्रदेश संगठन की कमान थामते ही भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी विपक्ष के समूल सफाए के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा के रणनीतिकार इसके लिए सधी चाल चल रहे हैं। उन्होंने माइक्रो प्लानिंग तैयार की है। इस प्लान के केंद्र में 35000 बूथ हैं, जिन पर पार्टी 80 सीटें जीतने की कुंजी तलाश रही है। वैसे भाजपा का विजय रथ 2014 के लोक सभा चुनाव से दौड़ रहा है लेकिन उसकी तुलना में 2019 में 73 से घटकर गठबंधन की सीटें 64 हुई और 2017 के विधान सभा चुनाव की 325 से घटकर 2022 में हुई 255 सीटों ने अलार्म बजा दिया, जिसे पार्टी कतई नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। इस वर्ष हुए विधान सभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद भाजपा ने मिशन 2024 की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए 2014 से 2022 तक के चुनाव परिणामों की बूथवार समीक्षा की गई है। भाजपा इस सवाल पर भी मंथन कर रही है कि किन समीकरणों के चलते 2019 और फिर 2022 में तुलनात्मक रूप से सीटें कुछ घटीं। ऐसे में निष्कर्ष यह निकला कि प्रदेश के कुल पौने दो लाख बूथों में से एक लाख बूथ ऐसे हैं, जिन पर भाजपा 2014 से लेकर लगातार जीत रही है। यहां विपक्ष की किसी रणनीति का असर नहीं दिखाई दिया है। वहीं, करीब 40 हजार बूथ ऐसे मिले, जिन पर भाजपा को वोट न के बराबर मिला। वहां अलग-अलग विपक्षी दल और नेताओं का मजबूत प्रभाव है। अब जो उतार-चढ़ाव चुनावों में आया, उसके लिए जिम्मेदार रहे मात्र 35000 बूथ। यहां कभी भाजपा का जादू चला, कभी सपा ने अपना प्रभाव जमाया तो कभी यहां का वोटर बसपा की ओर खिसक गया।

मंथन: सवालों के हल खोज रहे दिग्गज

इस सवाल पर भी मंथन किया जा रहा है कि 2017 के विधान सभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन, 2019 के लोक सभा चुनाव में सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन और फिर 2022 में सपा, रालोद, सुभासपा, प्रसपा, अपना दल कमेरावादी आदि दलों के गठबंधन के बावजूद भाजपा को पूर्ण बहुमत पाने से विपक्ष क्यों नहीं रोक सका।

लाभार्थियों पर नजर

भाजपा ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क बनाए रखने की रणनीति बनायी है ताकि वहां सेंध लगाने का विपक्ष का प्रयास सफल नहीं हो पाए।

उपचुनाव में जीत से बढ़ा उत्साह

भाजपा ने हाल ही हुए लोक सभा उपचुनाव में सपा से यादव-मुस्लिम गठजोड़ वाली आजमगढ़ और मुस्लिम के निर्णायक वोट वाली रामपुर सीट अपनी रणनीति से छीन ली। इससे भगवा खेमे का उत्साह काफी बढ़ा है। इस तरह वर्तमान में भाजपा गठबंधन की 64 सीटें हो गई हैं। शेष बची 14 सीटों में से दो को वह कमजोर होते देख रही है। माना जा रहा है कि सपा के वयोवृद्ध संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब शायद मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ें और रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी संभवत: इस बार प्रत्याशी नहीं होंगी। तब उनके स्थान पर चुनाव लड़ने वाले किसी भी अन्य प्रत्याशी को परास्त करना भाजपा के लिए अधिक आसान होगा।

भाजपा रणनीतिकारों का मानना है कि जिन 35 हजार बूथों को लेकर कोई पार्टी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है वहां यदि डेढ़ वर्ष मेहनत की जाए तो भाजपा उन्हें अपने पक्ष में कर सकती है। इसके बाद सिर्फ 40 हजार बूथ बचेंगे, जिन पर सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद और अन्य दलों का आपसी संघर्ष होता रहेगा। इस तरह भाजपा के पास सभी 80 सीटें जीतने की पूरी संभावना है।

और ज्यादा ताकतवर हो गए संजय प्रसाद

» सीएम योगी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के पास अब बड़ी और अहम जिम्मेदारी

» प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना, दोनों की जिम्मेदारी एक साथ निभाएंगे

» स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जताई थी नाराजगी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बड़े अफसरों के पद में बदलाव होने के बाद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उथल-पुथल मच गई है। खास बात यह है कि पद के लिहाज से बेशक मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का पद प्रदेश का सबसे बड़ा पद माना जाता है लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस के एजेंडे के हिसाब से गृह और सूचना सबसे अहम पद हैं। जो इस पद पर बैठता है, उसका कद सबसे बड़ा होता है। इस पद पर अब संजय प्रसाद नजर आएंगे।

दरअसल, एक सितंबर की सुबह यूपी ब्यूरोक्रेसी में अचानक बड़ा बदलाव हुआ। यूपी के टीम 9 में कई अहम नौकरशाहों को अचानक ही बदल दिया गया, लेकिन इस बदलाव में एक अहम चीज जो दिखाई दी, वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद सबसे ताकतवर होकर उभरे। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना, दोनों की जिम्मेदारी एक साथ दे दी गई। यह वही पद है जो कभी अवनीश अवस्थी के पास एक साथ हुआ करता था। यानी 2017 से 2022 के दौरान जिस पद और जिस कद के साथ अवनीश अवस्थी, योगी के सबसे ताकतवर नौकरशाह थे, अब वही पद और कद संजय प्रसाद का होगा। लगभग तीन सालों से संजय प्रसाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव होने के साथ सीएमओ की जिम्मेदारी भी देखते रहे हैं। यही नहीं वो सचिव सूचना के पद पर भी तैनात रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के सबसे खासमखास अधिकारियों में शुमार है संजय प्रसाद। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। संजय प्रसाद फिटनेस फ्रिक्र भी हैं। हर दिन सुबह कई किलोमीटर टहलना उनकी आदत में शुमार है। अपने तमाम व्यस्त कामों के बावजूद वह फिटनेस के अपने नियम को नहीं तोड़ते हैं।

डाटा मैन माने जाते हैं संजय प्रसाद

संजय प्रसाद की खासियत है कि आंकड़ों में उन्हें महारत हासिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास आंकड़ों के साथ अगर कोई कागज भेजना होता है तो संजय प्रसाद के जरिए जाता है क्योंकि माना जाता है विभाग चाहे कोई हो डाटा या आंकड़ा संजय प्रसाद से गुजर कर आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आसपास अगर साए की तरह कोई एक अधिकारी मौजूद होता है तो उनका नाम संजय प्रसाद है। वह चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे लोकभवन में मुख्यमंत्री का कार्यालय हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यात्राएं हों। संजय प्रसाद चलते-फिरते मुख्यमंत्री के दफ्तर के रूप में उनके साथ होते हैं। कोरोना के भयावह हालात के बीच संजय प्रसाद योगी आदित्यनाथ के सबसे करीब रहे। चाहे कोविड के दौरों में साथ रहना हो या सरकारी और राजनीति की यात्राएं हो, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर संजय प्रसाद हमेशा नजर आते थे। नवनीत सहगल को जब एसीएस सूचना बनाया गया था, तब सचिव के तौर पर सूचना विभाग में मुख्यमंत्री के आंख-कान थे। अब जब संजय प्रसाद को गृह और सूचना दोनों का प्रमुख सचिव बनाया गया है तो माना जा रहा है कि उन्हें भी अवनीश अवस्थी की तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताकत सौंपी है।

स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए अमित मोहन नवनीत सहगल का घटा कद

प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादलों में गड़बड़ी पर घिरे अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से स्वास्थ्य विभाग छीन लिया गया है जबकि सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कद घटाते हुए उनका तबादला खेलकूद विभाग में किया गया है। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला के कार्यकाल में यूपी बोर्ड का पेपर लीक होने के बाद उन्हें आयुष विभाग भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग में तबादले को लेकर सरकारी की किरकिरी होने और डिप्टी सीएम बृजेश पाठक के दखल के बाद अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद को हटाया गया है। स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा था कि बिना उनकी जानकारी के तबादले किए गए। अमित मोहन अब, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के साथ खादी तथा हथकरघा विभाग देखेंगे। इनके स्थान पर केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद प्रदेश लौटे प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का काम सौंपा गया है। अपर मुख्य सचिव सूचना, खादी एवं ग्रामोद्योग व एमएसएमई का पद संभाल रहे नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण के पद पर भेजा गया है। नवनीत सहगल को महत्वपूर्ण पदों से हटाना योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

गंगा प्रदूषण पर कोर्ट की सख्ती के मायने

"सवाल यह है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं हो सकी ? आखिर कोर्ट को खर्च धनराशि का हिसाब देने में आनाकानी क्यों की जा रही है? आदेश के बावजूद अधिकारी गंगा प्रदूषण पर तैयार की गयी बीएचयू और कानपुर आईटी की रिपोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहे हैं?

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने में बरती जा रही कोताही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने न केवल नदी के प्रदूषण रिपोर्ट में की जा रही लीपापोती पर सवाल उठाए हैं बल्कि नमामि गंगे योजना में खर्च धनराशि का हिसाब उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी भी जतायी है। कोर्ट ने इसे आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं हो सकी? आखिर कोर्ट को खर्च धनराशि का हिसाब देने में आनाकानी क्यों की जा रही है? आदेश के बावजूद अधिकारी गंगा प्रदूषण पर तैयार की गयी बीएचयू और कानपुर आईटी की रिपोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहे हैं? आज भी गंगा में बिना संशोधित सीवर क्यों बहाया जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार ने पूरी योजना को पलीता लगा दिया है?

नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे केंद्र सरकार ने जून 2014 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ इसके अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करना है। इसके लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में करोड़ों का प्रावधान करती है। कार्यक्रम के आठ साल बाद भी गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकी हैं। बीएचयू और कानपुर आईटी ने अपनी रिपोर्ट में गंगा के प्रदूषण पर चिंता जतायी है। अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और तीन जजों की पूर्ण पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। पिछले दिनों कोर्ट ने योजना में खर्च की धनराशि का हिसाब मांगा था लेकिन नमामि गंगे योजना के निदेशक ने हिसाब नहीं दिया है। वहीं केंद्र व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी प्रदूषण रिपोर्ट पेश करने में आनाकानी कर रहे हैं। साफ है गंगा को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि आज भी गंगा में सीवर का पानी सीधे गिराया जा रहा है। यूपी में गंगा 26 जिलों से होकर बहती है लेकिन सीवर के पानी को संशोधित करने के लिए मात्र 35 एसटीपी लगाए गए हैं। इसमें भी कई बेकार पड़े हैं। वहीं 15 शहरों में एसटीपी तक नहीं लगाए गए है। वहीं चमड़ा और अन्य उद्योगों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी भी सीवर के जरिए गंगा में बहाया जा रहा है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें गंगा को निर्मल और अविरल करना चाहती है तो उन्हें न केवल संबंधित विभागों को जवाबदेह बनाना होगा बल्कि लापरवाह लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी अन्यथा स्वच्छ गंगा बस सपना भर होगा।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार

नीरज कुमार दुबे

जो लोग भारत में मंदी की बात करते हैं उन्हें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी जीडीपी के आंकड़ों पर गौर करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई है? एनएसओ के आंकड़ें कुछ और कहानी कहते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। देश में बेरोजगारी भी कम हो रही है क्योंकि सरकार की नीतियों की बदौलत रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन का भी देश नया रिकॉर्ड बनाने वाला है यानी विकास परियोजनाओं में पैसा बाधक नहीं होगा। यह भी माना जा रहा है कि आरबीआई ने जो कदम पिछले दिनों उठाये हैं उसके चलते महंगाई भी जल्द कम होगी। बहुत-सी वस्तुओं के दामों में तो कमी आने की शुरुआत हो भी चुकी है। जरूरी खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने के अलावा जिस तरह दलहनों और चना का आवंटन राज्यों को बढ़ाया गया है उससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यही नहीं खाद्य तेलों के दामों में कमी के सरकारी प्रयास पहले ही रंग ला चुके हैं।

चिंता इस बात की है कि हम तो तेज तरक्की कर रहे हैं लेकिन दुनिया पिछड़ रही है। अगर दुनिया ऐसे ही पिछड़ती रही तो हमारे लिये मुश्किल हो सकती है। यह बात इस आंकड़े से समझिये। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत रही वहीं इसी तिमाही में चीन की वृद्धि दर 0.4 प्रतिशत रही है। ऐसा ही हाल दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का है। यदि हमारे और अन्यों के बीच यह अंतर इसी तरह बरकरार रहा तो मुश्किल हो सकती है। भारत की जीडीपी अब महामारी यानी कोरोना काल से पहले के स्तर से करीब चार प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा जिस तरह से वृद्धि को खपत से गति मिली है उससे संकेत मिलता है कि खासकर सेवा क्षेत्र में घरेलू मांग पटरी पर आ रही है। महामारी के असर के कारण दो साल तक विभिन्न पाबंदियों के बाद अब खपत बढ़ती दिख रही है। लोग खर्च के लिये बाहर आ रहे हैं। सेवा क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है और आने वाले महीनों में त्योहारों के दौरान इसे और गति मिलने की उम्मीद है। अब जीडीपी आंकड़ा बेहतर होने से रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को काबू में लाने पर ध्यान दे सकेगा। उल्लेखनीय है कि खुदरा महंगाई दर अभी

आरबीआई के संतोषजनक स्तर यानी छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निजी निवेश सालाना आधार पर 20.1 प्रतिशत बढ़ा। सरकारी खर्च इस दौरान 1.3 प्रतिशत जबकि निजी खपत 25.9 प्रतिशत बढ़ी है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, सकल मूल्यवर्धन इस साल अप्रैल-जून तिमाही में 12.7 प्रतिशत रहा। इसमें सेवा क्षेत्र में 17.6 प्रतिशत, उद्योग में 8.6 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहां तक बेरोजगारी के आंकड़ों की बात है तो शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2022 के दौरान सालाना आधार पर 12.6 प्रतिशत से घटकर 7.6 प्रतिशत रह गई है। देश में अप्रैल-जून, 2021 में कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण बेरोजगारी दर अधिक थी लेकिन अब नवीनतम आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महामारी की छाया से निकलकर अर्थव्यवस्था सुधार की ओर बढ़ रही है। आंकड़े दर्शाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु की) में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 9.5 प्रतिशत रह गई जो एक साल पहले की समान अवधि में 14.3 प्रतिशत थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में पुरुषों में बेरोजगारी दर एक साल पहले के 12.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून, 2022 में घटकर 7.1 प्रतिशत रह गई है। अर्थव्यवस्था के दूसरे मोर्चों की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि धीमी पड़कर 4.8 प्रतिशत रही जो चिंता का कारण है। इसके अलावा निर्यात के मुकाबले आयात का अधिक होना भी चिंताजनक है। साथ ही विकसित देशों में मंदी की आशंका से आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर की गति धीमी पड़ने की आशंका है। बहरहाल, इन आंकड़ों पर गौर करें तो माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की ओर बढ़ रही है। सरकार को बस चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4 प्रतिशत पर बनाए रखना होगा। यह आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नरमी के संकेतों के बीच भारत की वृद्धि दर बेहतर होने से वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और देश में निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

बढ़ती मुश्किलों के बीच इमरान की चुनौती

जी. पार्थसारथी

लग रहा है कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर परिवारों में एक से आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पदचिन्हों पर हैं, जो इन दिनों लंदन में आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नवाज शरीफ पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला पाकिस्तान में चल रहा है। यह तथाकथित आर्थिक अपराध खासतौर से सऊदी अरब स्थित उनकी स्टील मिल को लेकर बताया गया है। यह दोष नवाज शरीफ पर 2018 में राष्ट्रीय चुनाव में हार के बाद लगा, जब इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री उनकी जगह ली। इमरान खान की जीत के पीछे का एक तथ्य यह भी था कि उस वक्त वे पिछले कई सालों से सैन्य प्रतिष्ठान के पसंदीदा नेता थे। बता दें कि सऊदी अरब में स्टील मिल नवाज शरीफ को विरासत में मिली है। शरीफ खानदान काफी लंबे समय से सऊदी सुल्तानशाही का अंतरंग परिवार है।

रिवायती रूप से भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन इनको उस वक्त झटका लगा जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की और मलेशिया के नेतृत्व में बने नए इस्लामिक संगठन से जुड़ने का मन बनाया, जिसका मकसद इस्लामिक जगत को नया आयाम देना रहा है और इससे सऊदी अरब की सरदारी कमतर बनती है। लगता है इमरान खान को इस्लामिक जगत की अंदरूनी राजनीति के बारे में जानकारी कम है। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की तिकड़ी बनने पर सऊदी अरब का खार खाना स्वाभाविक था और जिन पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति वह पाकिस्तान को घटी दरों और उधार पर करता आया है, उसमें अड़ंगा लगना ही था। ऐसे में पाकिस्तान को ऐसा कोई अन्य देश मिलना लगभग नामुमकिन था, जो दयनीय आर्थिक स्थिति में सऊदी अरब जितना मददगार होता। जब भी पाकिस्तान में शरीफ खानदान की सरकार आई तो प्रधानमंत्री सबसे पहले सऊदी अरब की यात्रा पर गए और यही शाहबाज़ शरीफ ने भी किया ताकि सऊदी अरब के राजपरिवार से संबंध फिर से मधुर बन सकें। उनकी यात्रा के बाद संकेत मिले कि सऊदी अरब पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देगा। नकदी का टोटा भुगत रहे पाकिस्तान के लिए यह खबर अच्छी है। सऊदी अरब के बाद शाहबाज़ शरीफ यूएई पहुंचे जो अप्रवासी पाकिस्तानी कामगारों के लिए रोजगार का सबसे प्रमुख स्रोत है। किंतु पाकिस्तान की आर्थिक मुसीबतें निरंतर बनी हुई हैं और विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। कोई हैरानी नहीं कि सेना ने संसद में इमरान खान को पटखनी दिलवाने में मदद की और शाहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार बनवा दी। परंतु पिछला हफ्ता शाहबाज सरकार के लिए मुसीबतज़दा रहा है। लगातार बढ़ते दामों ने राष्ट्रव्यापी नाराजगी को भड़काया है। इसके अलावा, इमरान खान की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनों ने गंभीर राजनीतिक अशांति मचा दी है। मामला उस वक्त संजीदा हुआ जब इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने 17 जुलाई को हुए उपचुनाव में 20 में से 15 सीटों पर कब्जा कर एक तरफा विजय हासिल कर ली। इस घटना को इमरान खान की सेनाध्यक्ष बाजवा पर निजी जीत की तरह भी देखा जा रहा है, जो जाहिर तौर पर शरीफ़ सरकार का साथ दे रहे हैं। यह जीत शाहबाज शरीफ के बेटे के लिए भी निजी पराजय बनी और उन्हें पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और अपनी जगह मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता चौधरी परवेज इलाही को देनी पड़ी।

सेनाध्यक्ष बाजवा की इमरान के प्रति नापसंदगी के बावजूद सेना का बड़ा तबका उनके द्वारा अमेरिका के प्रति दिखाई दृढ़ता से अंदर-ही-अंदर प्रशंसक बन चुका है। हालांकि असलियत से वाकिफ लोग समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद के बिना पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था वित्तीय रूप से ढह जाएगी। परंतु इस किस्म की मदद अमेरिका की सहायता के बिना संभव नहीं है और अमेरिका परस्त जनरल बाजवा यही इनायत पाने की कोशिश में हैं। वही मुल्क के अंदर जारी उठापटक में इमरान खान के विरोधी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन पर भी आर्थिक और अन्य अपराधों में केस दर्ज हों। जहां अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी मंडल ने पाकिस्तान को उबारने के लिए 39 महीनों की अवधि वाली 6 बिलियन डॉलर की सहायता देने को मंजूरी दी है वहीं आने वाले समय में सामाजिक खर्च में कटौती करना और ऋण की अन्य शर्तों को पूरा करना मौजूदा सरकार को राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय बना डालेगा। इन उपायों में, तनख्वाहें और पेंशनों में अतिरिक्त वृद्धि की मौजूदा योजना में बड़े बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी। पहले से बहुतेरी अंदरूनी चुनौतियां झेल रहे पाकिस्तान के लिए आने वाला समय उथल-पुथल भरा हो सकता है, अगले साल 2023 में आम चुनाव तय हैं। वहीं आने वाले महीनों में, जनरल बाजवा बतौर सेनाध्यक्ष अपनी पारी के अंतिम पड़ाव में होंगे। 29 नवम्बर को उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। यह तय है कि सरकार को जनता से जारी समर्थन से उत्साहित हुए इमरान खान से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जनरल बाजवा खुद की पसंद का अपना उत्तराधिकारी बनाना प्रस्तावित करेंगे। देखना यह है कि उनका उत्तराधिकारी और शाहबाज सरकार इमरान की बढ़ती लोकप्रियता से किस तरह निबटेंगे। भारत के साथ संबंध आगे भी जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को आईएसआई की परोक्ष-अपरोक्ष मदद से जुड़े रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान जानता है कि भारत को सीमा पार जाकर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने में हिचक नहीं होगी।

सूखापन एग्जिमा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि त्वचा जब अपनी नमी खो देती है तो उसमें जलन और सूजन होने लगती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की बिलकुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नीम का तेल है। जो इसका असरकारी इलाज है। तो चलिए जानते हैं नीम का तेल किस तरह एग्जिमा को ठीक करता है।

नीम के तेल में है एग्जिमा का इलाज

एग्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा के धब्बे लाल, सूखे,फटे और खुजली करने लगते हैं। ये सबसे सामान्य इंफ्लामेशन त्वचा विकार है। इसमें इतनी ज्यादा खुजली होती है कि खुजाने में त्वचा ही छिल जाती है। खुजलाने से एग्जिमा की बीमारी और ज्यादा खराब रूप ले लेती है लेकिन एग्जिमा का और खुजली का इलाज कई तरीकों से संभव है। एग्जिमा का मुख्य कारण हमारे जींस में होता है और ये आनुवांशिक कारणों की वजह से ज्यादा होता है। एग्जिमा से ग्रस्त लोग बहुत संवेदनशील होते हैं और इन्हें धूल, पराग, घर के पायदान, घरेलू रसायन और सौंदर्य प्रसाधनों से बड़ी जल्दी एलर्जी हो जाती है। अगर ठीक तरह से एग्जिमा का इलाज न किया जाए तो कुछ लोगों में ये अस्थमा और बुखार का रूप ले लेता है। एग्जिमा से ग्रस्त लोगों को ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो त्वचा पर गलत प्रभाव डालें। जैसे कि मौसम में बदलाव, पशुओं के नज़दीक जाना, तंग कपड़े पहनना, परफ्यूम, डिटर्जेंट,पसीना आदि। लेकिन सबसे ज्यादा आपको सूखेपन से बचना है।

तेल निकालने की विधि

नीम के पेड़ के बीजों और सुपारी से नीम का तेल निकाला जाता है। सदियों से लोग दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में नीम के तेल का प्रयोग करते आ रहे हैं। नीम का तेल न सिर्फ उपयोगी होता है बल्कि नीम के पेड़ के कई हिस्से जैसे बीज, जड़, फल और छाल का प्रयोग भी दवाओं में किया जाता है। नीम कई प्रकार के त्वचा रोगों का इलाज करने में सक्षम है क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेट्री यौगिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं जोकि त्वचा का लालपन और खुजली दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा नीम में एंटीबैक्टीरियल यौगिक भी होते हैं जो हर तरह के संक्रमण को दूर करते हैं।

मार्केट में ऐसी कई क्रीम उपलब्ध हैं जो एग्जिमा का ईलाज करने का दावा करती हैं लेकिन नीम ऐसे कई काम कर सकती है जो ये क्रीम नहीं कर सकती। सबसे खास बात ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। रिसर्च के मुताबिक नीम एग्जिमा के कई लक्षणों का इलाज करने में सक्षम है।

एलोवेरा भी फायदेमंद

एग्जिमा के सामान्य लक्षणों जैसे खुजली और जलन का इलाज एलोवेरा से किया जा सकता है। इस रसदार पौधे में एंटी-इंफ्लामेट्री यौगिक होते हैं, जो कि आपकी त्वचा को ठंडक और आराम पहुंचाता है। एलोवेरा त्वचा को नमी और हाइड्रेशन भी प्रदान करता है।

नीम का तेल लगाने का तरीका

सबसे पहले साबुन का इस्तेमाल करना बंद कर दें और उसकी जगह नीम के साबुन का प्रयोग करें। नीम के साबुन से एग्जिमा को छोड़कर त्वचा के कई विकारों का इलाज संभव है। आप अपने नहाने के पानी में भी नीम का तेल डालकर नहा सकते हैं। इससे त्वचा की सफाई होती है। नहाने में गुनगुने पानी का ही प्रयोग करें। नम त्वचा पर नीम क्रीम या नीम लोशन लगाएं। ये क्रीम को स्किन बैरियर को रीस्टोर करने में मदद करता है। नीम के तेल को सीधा प्रभावित हिस्से पर ना मलें। चूंकि, त्वचा पहले से ही जली और खराब होती है इसलिए उस पर सीधा नीम का तेल लगाने से परिस्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए एग्जिमा के लिए नीम का तेल खरीदने से पहले कुछ बातों को जान लेना बहुत जरूरी है। आपकी त्वचा को केमिकल फ्री, बढ़िया और नेचुरल प्रोडक्ट की जरूरत है। इसलिए आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है।

ऑलिव ऑयल भी उपयोगी

इस तेल में त्वचा की गहराई तक जाकर उसे मुलायम और पोषण देने की क्षमता होती है इसलिए ऑलिव ऑयल एग्जिमा का बेहतरीन इलाज है। अन्य तेलों के मुकाबले ऑलिव ऑयल ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें सब कुछ नैचुरल होता है और इससे बहुत ही कम लोगों को एलर्जी होती है। हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल करें।

हंसना मना है

एक लड़की के पढ़ते-पढ़ते सिर में दर्द हो गया लड़की दुकान पर गई। लड़की: भैया एक सिर दर्द की गोली देना: दुकानदार: ये लो मैडम 5 रुपये की है: लड़की भइया इसमें कोई और कलर वाली दिखाना। दुकानदार बेहोश।

पत्नी ने सुबह-सुबह पति को उठाया। पत्नी: सुनो जी, मैंने सपना देखा कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हैं। पति: तो फिर से एक बार सो जाओ और सपने में ही हार पहन भी लो।

अर्ज किया है.. जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की, मदहोश हो गए हम। पर जब पता चला नजर पर्मानेंट तिरछी है, वहीं खड़े-खड़े बेहोश हो गए हम।

मैडम बच्चों से: जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसे मैं जल्दी घर जाने दूंगी। तूफान सिंह ने तुरंत अपना बैग बाहर फेंक दिया। मैडम: ये बैग किसने फेंका। पप्पू: मैंने फेंका,अब घर जाने दो।

ऊंट और चींटी का प्रेम विवाह हुआ। अगले ही दिन ऊंट मर गया। चींटी बोली: वाह रे मोहब्बत, एक दिन का प्यार मिला और सारी उमर कब्र खोदने का काम मिला।

कहानी — शराब की लत

एक शराबी जो की बहुत ही ज्यादा पीता था। उसके पीने की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा था। घर के सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। एक दिन उसको किसी आदमी ने एक संत के बारे में बताया और बोला उनके पास जाओ वो तुम्हारी शराब पीने की बुरी आदत को छुड़ा देंगे। वह अगले दिन सुबह उस संत के पास पंहुचा और बोला बाबा मैं अपनी शराब पीने की लत से बहुत परेशान हो गया हूं। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। संत बोले, तुम ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते जब तुमको इतनी परेशानी है। वह बोला मैं तो शराब को छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये मुझको नहीं छोड़ती है। उसकी इस बात को सुनकर संत ने कहा कल सुबह आना तुम, तभी बात करूंगा। अगले दिन सुबह-सुबह वह संत के पास पहुंच गया, उसको अपनी तरफ आता देख बाबा ने एक पेड़ को जाकर जल्दी से पकड़ लिया। जब वह बाबा जी के पास पंहुचा तो उनको देखा की वो एक पेड़ को पकड़ कर खड़े हैं। शराबी ने संत को नमस्कार किया और बोला आप यह क्या कर रहे हो, तो बाबा ने जबाब दिया, ये पेड़ मुझको छोड़ नहीं रहा है। यह सुनकर वह शराबी चौंक गया और बोला बाबा आज मैंने पी नहीं है, आप ने पेड़ को पकड़ रखा है उसने नहीं। उसकी बात को सुनकर संत मुस्कुराया और बोला मैं तुमको यही बताना चाहता था की पेड़ ने नहीं मैंने उसको पकड़ रखा है, इसी तरह शराब ने तुमको नहीं बल्कि तुम ने शराब को पकड़ रखा है। शराबी की आंखें खुल गईं और वह बोला आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा।

शिक्षा: इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कोई भी बुरा काम अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से छोड़ा जा सकता है।

8अंतर खोजें

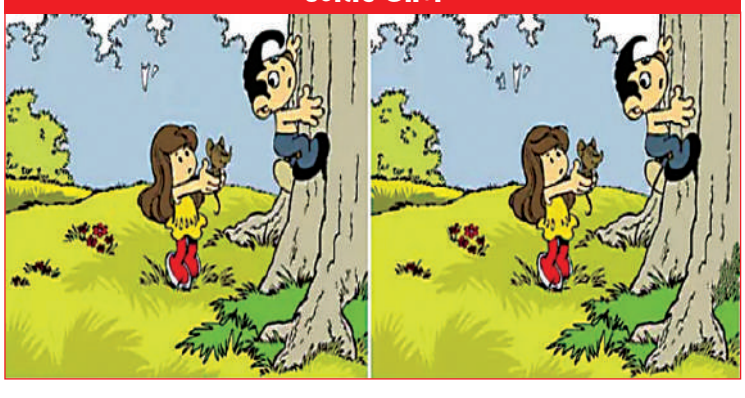

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — निजी समस्या सुलझ सकती है। काम-धंधा भी अच्छा चलेगा। दोस्तों से मिलने की कोशिश करेंगे।

वृषभ — दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। अटके हुए कामकाज पूरे होने से धन लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन — अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ नए काम या कोशिश कर सकते हैं। जो नए ऑफर मिलेंगे उन पर विचार करें।

कर्क — मानसिक परेशानियां व दौड़-भाग भी रहेगी। कुछ अपेक्षित लोगों से सहयोग नहीं मिलने के कारण दुखी हो सकते हैं।

सिंह — आपको किसी की मदद की जरूरत भी रहेगी। जीवनसाथी से मतभेद हो सकते हैं।

कन्या — आप खर्चे में अति करने से बचें। जोश में आपकी जेब भी खाली हो सकती है। आपकी परेशानी बढ़ने के योग हैं।

तुला — आपकी भावनाएं भी चेहरे पर साफ नजर आएंगी। लिहाजा अच्छा सोचें और अच्छे ही काम करें।

वृश्चिक — पैसों के क्षेत्र में नई और सकारात्मक शुरुआत वाला दिन कहा जा सकता है। फायदा होने के भी योग हैं।

धनु — पुराने दोस्तों से बातचीत हो सकती है। किसी अच्छे दोस्त से सलाह मिल सकती है। काम पूरे होने के योग हैं।

मकर — कुछ अपेक्षित लोगों से सहयोग नहीं मिलने के कारण दुखी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा अफेयर शुरू हो सकता है।

कुम्भ — अपनी उदारता पर कंट्रोल करें। पैसों से जुड़ी कोई बड़ी टेंशन हो सकती है। किसी बड़े काम में घबराहट भी रहेगी।

मीन — रोजगार के मामले में किसी से सलाह जरूर करें। पार्टनरशिप में भी फायदा होने के योग बन रहे हैं।

लाल सिंह चड्ढा बायकॉट के बाद आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा

सब इंसान हैं और इंसान से ही होती है गलतियां

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी सुर्खियों में बनें हुए हैं। आमिर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तहर से पिट गई हैं। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से बायकॉट किया जा रहा है। इसके बाद रिलीज होने वाली फिल्में भी अब लोगों के निशाने पर आती नजर आ रही हैं। लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के बाद स्टार्स के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। वहीं अबतक आमिर इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे थे। वहीं अब पहली बार आमिर ने अपना रिएक्शन दिया है। आमिर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कई सारी फीलिंग्स के बारे में बात की है।

बॉलीवुड | मसाला

एक्टर आमिर खान ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में आमिर मिच्छामि दुखणम के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं, जो जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व है। आमिर खान के इस वीडियो की शुरुआत में शाहरुख खान की फिल्म कल हो न हो का म्यूजिक सुनाई देता है। इसके बाद एक शख्स की आवाज आती है। वो कहता है, 'मिच्छामि दुखणम... सब इंसान हैं, और गलतियां इंसान से ही होती है। कभी बोल सेए कभी हरकतों से, कभी अनजाने में, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, कभी नहीं बात करने से। अगर मैंने कभी भी किसी तरह से आपका दिल दुखाया है तो मन, वचन, काया से आपसे क्षमा मांगता हूं। आमिर खान के इस वीडियो पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। कोई आमिर को सपोर्ट तो कोई ट्रोल करता दिख रहा है।

बॉलीवुड | मन की बात

मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आई कटरीना : विक्की

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल को फिल्मफेयर में बेस्ट एक्टर क्रिटिक के अवॉर्ड से नवाजा गया है। उनको ये अवॉर्ड सरदार उधम में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। विक्की को अवॉर्ड मिलने पर कटरीना कैफ सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिखीं। साथ ही इवेंट में विक्की ने कटरीना के लिए गाना भी गाया। अवॉर्ड जीतने के बाद विक्की ने स्टेज से सबको धन्यवाद देते हुए कहा आई लव यू मॉम-डैड। आई लव यू कटरीना कैफ..। आप मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आई हो। वहीं उन्होंने अपने भाई सनी का भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा विक्की ने अवॉर्ड शो में अपनी परफॉर्मेंस के लिए इरफान खान को ट्रिब्यूट भी दिया। उन्होंने कहा ये मेरा पहला फिल्मफेयर है। ये बहुत ही खास है। हम सभी के लिए ये एक खास फिल्म थी। मैं शूजीत दा को धन्यवाद देता हूं। इस फिल्म में मेरी एक्टिंग इरफान खान को श्रद्धांजलि है। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। विक्की के इस अंदाज को उनके फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। विक्की कौशल की फिल्म सरदार उधम भारतीय क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह की बायोपिक है। इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को ब्रिटेन में मार दिया था। उधम सिंह ने ऐसा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किया था। जनरल ओ डायर ने ही इस गोलीकांड के आदेश दिए थे। इस फिल्म का निर्देशन शूजित सिरकार ने किया है।

कार्तिक एक साल से हैं सिंगल

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने हाल ही में फिल्म कम्पैनियन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलासा किया। कार्तिक अक्सर एक्ट्रेस सारा अली खान संग ब्रेकअप की खबरों की वजह से चर्चा में रहते हैं। लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी लव लाइफ के बारे में बात की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो अब सिंगल हैं। कार्तिक ने कहा मैं पिछले सवा साल से सिंगल हूं। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इस पर उनसे कहा गया कि वो टाइमलाइन को लेकर काफी स्पेसिफिक हैं, तो वो शरमा गए और कहने लगे कि वो पिछले 1 साल से सिंगल हैं। इसके बाद कार्तिक से पूछा गया कि क्या वो आगे भी यही कहेंगे कि उनका काम ही उनकी रिलेशनशिप है। इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिंगल हूं। बस इतनी सी ही बात है। सारा ने कुछ साल पहले कॉफी विद करण में अपने पिता सैफ अली खान के सामने कहा था कि उन्हें कार्तिक पर क्रश है। साथ ही सारा ने कार्तिक को डेट करने की इच्छा भी जताई थी। ऐसे में जब दोनों ने लव आज कल 2 में साथ काम किया तो इनके अफेयर को लेकर अफवाहें जोर पकड़ने लगीं। हालांकि फिल्म की रिलीज के बाद दोनों के अफेयर की खबरें भी हवा हो गईं। खबरें तो यहां तक आईं कि कार्तिक ने सारा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। कार्तिक के

बॉलीवुड | गपशप

वर्कफ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा की शूटिंग में बिजी हैं।

बिना जिम गए शुद्ध देसी अंदाज से खुद को बनाया मजबूत

ना जिम गए ना प्रोफेशनल से डाइट प्लान बनवाया, ना किसी महंगे ट्रेनर पर पैसे बर्बाद किए, अपने बलबूते खुद को इतना मजबूत किया कि एक नहीं कई बार रिकॉर्ड कायम किया। कुछ लोगों की सफलता उन लोगों के लिए मिसाल होती है जो लोग संसाधनों की कमी को अपनी सफलता की राह का रोड़ा बताते हैं। पंजाब के एक होनहार युवा ने शुद्ध देसी अंदाज से खुद को विश्व विजेता बनाया, जो आज के युवाओं के लिये एक प्रेरणा स्रोत साबित हो रहा है।

पंजाब के 20 साल के कुंवर अमृतबीर सिंह ने एक मिनट में तालियों के साथ सबसे ज्यादा फिंगर टिप पुश अप्स कर गिनील वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। बिना जिम और डाइट के ऐसी बॉडी बनायी की लोगों के लिए मिसाल बन गए। देसी स्टाइल का खान पान और देसी अंदाज के कसरत कर उन्होंने यह कारनामा किया। अमृतबीर का कहना है कि वो कोई स्ट्रिक्ट डाइट रूल फॉलो नहीं करते। बल्कि घर का बना रेगुलर खाना जैसे- शुद्ध देसी घी, दूध, दही और पंजाबी स्टाइल पराठे उनके फेवरेट हैं और कसरत के लिए घरेलू जिम के तौर पर ईंट, रेत के बोरे और सीमेंट के प्लास्टिक कैंस हैं जो इनकी मजबूती का राज है। गुरदासपुर के रहने वाले कुंवर अमृतबीर सिंह जिनकी उम्र महज 20 साल है। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों के बल पर तालियों के साथ एक मिनट में सबसे ज्यादा पुश अप्स लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अमृतबीर ने फरवरी में अपना ये कारनामा अटेम्प्ट किया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जुलाई में जाकर सर्टिफाइड किया। अमृतबीर ने पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 11 नवंबर 2021 को कोशिश की थी लेकिन तब वो डिस्क्वालिफाई हो गए थे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि दोगुने जोश के साथ अपनी प्रैक्टिस और मेहनत में जुट गए। और नतीजा ये निकला कि वो एक के बाद एक कई वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रहे। अमृतबीर ने अपना पहला रिकॉर्ड 17 साल की उम्र में बनाया था।

अजब-गजब | 31 अगस्त को मैप से हटाया गया जहरीला टाउन

वो कस्बा, जहां सांस लेने भर से हो जाती है मौत

दुनिया में कई जगहें अलग-अलग कारणों से मशहूर हैं। कुछ अपनी खूबसूरती की वजह से, कोई इतिहास तो कोई कुछ और ही कारण से। आज हम जिस जगह की बात करने जा रहे हैं, वो अब वीरान है। अथॉरिटी ने 31 अगस्त को ये पूरा टाउन खाली करवा दिया। लोगों को कहा गया था कि डेडलाइन तक शहर को खाली करना है। इसकी वजह है कि अब ये जगह इंसानों के लिए बिलकुल सेफ नहीं है। इसे हमेशा-हमेशा के लिए खाली करवा दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के विट्टेनुम को माइनिंग टाउन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब इसे ऑस्ट्रेलिया का चेर्नोबिल कहा जाने लगा है। बताया जा रहा है कि इस शहर की हवा इतनी जहरीली हो गई थी कि यहां सांस लेना मुश्किल हो गया था। यहां सांस लेने पर जान जाने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा था। इस वजह से टाउन से सारे रेसिडेंट्स को निकाल कर इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। अब इस टाउन को मैप से हटाने की भी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। विट्टेनुम क्लोजर एक्ट के तहत लोगों को 31 अगस्त तक शहर खाली करने का अल्टीमेटम मिला था। लोगों को वार्निंग दी गई थी कि या तो खुद शहर छोड़ दें या उन्हें जबरदस्ती निकाला जाएगा। इस टाउन में 1943 से कई परिवार आकर बसने लगे थे। माइनिंग एरिया होने की वजह से यहां कई तरह जहरीली गैसों का रिसाव होता था। इस वजह धीरे-धीरे कई लोगों की जान जाने लगी। 1966 में लॉस और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से विट्टेनुम माइन को बंद कर दिया गया। यहां माइनिंग को बैन कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसके बाद भी लोगों ने एरिया को खाली नहीं किया। नतीजा कि यहां रहने वालों में करीब दो हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। यानी यहां रह रहे हर दस में एक की मौत हो गई। स्टडीज के मुताबिक माइन में काम करने वाले लगभग हर कर्मी की मौत हो चुकी है। इसके बाद 2006 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि विट्टेनुम से टाउन का तमगा छीन लिया जाएगा। 2007 में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब 31 अगस्त को इस टाउन में रहने वाले आखिरी शख्स ने भी इसे खाली कर दिया और अब ये बंद कर दिया गया है।

गरीब और किसान विरोधी है भाजपा सरकार : अखिलेश

» सत्ता संरक्षित अपराधी कर रहे बहन-बेटियों पर अत्याचार

» खतरे में सामाजिक सद्भाव महंगाई-बेरोजगारी बढ़ी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के कारण सामाजिक सद्भाव खतरे में है। तनाव से यूपी में डर व्याप्त है। सांप्रदायिक कुप्रचार पर लगाम नहीं है। ऐसे में प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? भाजपा राज में न तो आपराधिक घटनाओं को सही से दर्ज किया जाता है और न अराजकतत्वों पर अंकुश लगता है। महिलाएं लगातार अपमानित हो रही हैं और बच्चियां सबसे ज्यादा दुष्कर्म की शिकार हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि निर्दोषों का उत्पीड़न होता है और दोषियों का बाल बांका भी नहीं होता है। क्या यही लोकराज है? भाजपा राज में महिला अपराध में यूपी नंबर वन है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों में जंगलराज साफ दिखाई पड़ता है परंतु भाजपा को आधी-अधूरी रिपोर्ट का ढोल पीटने में संकोच नहीं है। उन्होंने कहा कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार वर्ष 2021 में 56,869 शिकायतें दर्ज हुईं। इसके मुताबिक रोज 350 साइबर क्राइम के मामले आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के तहत यूपी में आत्महत्या के मामले 2020 के मुकाबले 23 प्रतिशत बढ़े है। 2021 में 5,932 ने आत्महत्या की। सत्ता संरक्षित अपराधी बहन-बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिस दिन कहा छेड़छाड़ के कारण स्कूल नहीं जाने वाली छात्राएं भयमुक्त हैं उसी दिन राजधानी में लखनऊ के गोमतीनगर में छेड़खानी से तंग कक्षा आठ की छात्रा ने स्कूल छोड़ने की खबर सुर्खियों में थी। सच यह है कि भाजपा नेतृत्व को न तो उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब है और न प्रदेशवासियों को भयमुक्त वातावरण देने की क्षमता है। भाजपा पूरी तरह पूंजीवादी चरित्र की पार्टी है। जनता को महंगाई की चक्की में पीसने के अलावा भाजपा सरकार ने जीएसटी, इनकम टैक्स के माध्यम से गरीबों और मध्यम वर्ग का खून चूसकर जहां पिछले 7वर्षों में 11 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपति मित्रों का माफ किया गया है। वहीं गरीब को स्वास्थ्य-शिक्षा के मामलों में अनाथ छोड़ दिया गया है। जनता इस गरीब, किसान, नौजवान विरोधी सरकार को कब तक बर्दाश्त करेगी?

इस्तीफा देने की जगह फिर विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत

» विधान सभा सत्र बुलाने का लिया निर्णय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर बीते एक सप्ताह से झारखंड में कायम सस्पेंस के बीच सरकार ने विधान सभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय किया है। गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। विधान सभा का विशेष सत्र निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा होगी और सरकार सदन का विश्वास हासिल करेगी। चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी से निपटने के लिए विश्वास मत हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। सत्र से पूर्व छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सारे विधायक रांची वापस लौट आएंगे। फिलहाल रायपुर के पांच सितारा मेफेयर रिसार्ट में कुल 33 विधायक कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा सत्तापक्ष ने झारखंड राजभवन पर चुनाव आयोग का निर्णय स्पष्ट करने को लेकर भी दबाव बनाया।

अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल : संबित पात्रा

» कमीशन लेकर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिए गए शराब के ठेके

» आप के प्रचार के लिए विधान सभा का किया जा रहा दुरुपयोग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को कट्टर ईमानदार बताते थे जो चार महीने से ईडी की हिरासत में हैं। इसी तरह केजरीवाल ने पंजाब सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने की कोशिश की।

उन्होंने कहा कि जिस समय दिल्ली सरकार शराब नीति बनाने की शुरुआत कर रही थी, उसी समय पत्र लिखकर उन्हें ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की जानकारी दी गई थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें ठेके दिए गए। उन्होंने पूछा कि जिन खुदरा विक्रेताओं को केवल दो फीसदी का कमीशन दिया जाता था, उसे बढाकर 12 फीसदी क्यों किया गया? उन्होंने शराब की पुरानी कीमत और नई कीमत की तुलना करते हुए बताया कि शराब की बिक्री पर सरकार का कमीशन जानबूझकर कम किया गया और कंपनियों का कमीशन बढ़ाया गया। इसके बदले आम आदमी पार्टी ने कमीशन लिया है। वहीं केजरीवाल विधान सभा का दुरुपयोग कर अपना राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं।

किसानों की आय बढ़ाएगी ड्रोन तकनीक: शाही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए हर नई तकनीक को खेत तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों के समय, धन और श्रम की बचत हो। ड्रोन तकनीक कृषि का कायाकल्प करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हानिकारक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को घटाकर उनके स्थान पर तरल नैनो यूरिया व उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देगी। एक एकड़ भूमि के लिए नैनो यूरिया के आधे लीटर का घोल पर्याप्त है। नैनो तरल दवाओं तथा उर्वरकों के उपयोग से मानव स्वास्थ्य तथा मिट्टी दोनों को बचाया जा सकता है।

विपक्ष को एकजुट कर रहे नीतीश-केसीआर भाजपा हो जाएगी साफ: कुशवाहा

» सरकार में परिवर्तन को साथ आ रहीं पार्टियां, समाज को तोड़ रही भाजपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कटिहार। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोक सभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेलंगाना के सीएम केसीआर कर रहे हैं। लगातार दोनों में मंत्रणा हो रही है। देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है। अगले लोक सभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह साफ हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीति के कारण जनता नाराज हैं। देश की जनता का भाजपा से मोह भंग हो गया है। विपक्षी पार्टियां सरकार में परिवर्तन कराने के लिए लगातार एकजुट हो रही है। राज्य में भी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम किया जा रहा है। भाजपा समाज को तोड़ने का काम कर रही है। महागठबंधन समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। राज्य मंत्रिमंडल में दागी मंत्री होने संबंधी सवाल के जवाब में उनहोंने कहा कि आरोप किसी पर लग सकता है। राज्य सरकार किसी भी दोषी को बचाने का काम नहीं करेगी। महागठबंधन सरकार विधि सम्मत नीति पर चल रही है। इस अवसर पर जदयू के पूर्व अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, उमाकांत आनंद, शिव प्रकाश गरोदिया आदि मौजूद रहे।

तो दिल्ली दरबार कर रहा यूपी सरकार को परेशान!

» 4पीएम की परिचर्चा में उठे कई सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर नौकरशाही के तबादलों तक तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के बीच शीत युद्ध की खबरें सामने आती रहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली दरबार यूपी दरबार को परेशान क्यों कर रहा है? इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे, अनुपम मिश्रा, सैयद कासिम, अमिताभ श्रीवास्तव, शीतल पी सिंह और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने एक लंबी परिचर्चा की।

सुशील दुबे ने कहा अरविंद शर्मा जैसे नेता आधे घंटे में दिल्ली से लखनऊ आ गए थे कि ये विभाग मिलेगा वो मिलेगा पर छह महीने लग गए गणित बिठाने में। अब आदेश सेकेंडों में हो जाता है। कई एक्सटेंशन हुए भी हैं। अवस्थी की बांडिंग हो गई थी लेकिन सबसे बड़ा फायदा पाठक का हुआ है। अमित मोहन प्रसाद किनारे कर ही दिए गए।

परिचर्चा
रोज शाम को छह बजे देखिए 4PM News Network पर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा

अनुपम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्ट किया है। साउथ से लेकर नार्थ तक प्रचारक के तौर पर उनका इस्तेमाल किया। हिंदुत्व के नाम पर बढ़ाया है। मोदी खुद केंद्र में बैठकर चरखा काटने लगते हैं। ये बाण जिस धनुष से चल रहे हैं वो धनुष सेकुलर है। ये बाण हिंदुत्व लिए नजर आते हैं। दिल्ली और लखनऊ में कुछ तो चल रहा है। सैयद कासिम ने कहा कि इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं किया कि कंपनी पर ताला लगा दें। वे देख रहे कि हमारे ब्रांड को पीछे छोड़ रहे हैं। अपना ब्रांड बना रहे। इस पर कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स है वे पेंच कसने लगते हैं ताकि समय पर खुद के ब्रांड को बचाया जा सके।

अमिताभ श्रीवास्तव ने कहा कि रस्साकसी चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच। अगर आप अपने चहेते व करीबी का एक्सटेंशन नहीं करा पाए तो आप कमजोर हो रहे है। पीएमओ से कंट्रोलिंग हो रही है। ये तो साफ है। शीतल पी सिंह भी परिचर्चा में शामिल हुए।

गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-1 में अवैध निर्माण का मामला

सीलिंग व ध्वस्तीकरण का आदेश वीके सिंह की जेब में!

» माइन्स का काम करने वाले सिंह के आगे एलडीए अफसर नतमस्तक

» एलडीए की आंखों में धूल झोंक हो रहा अवैध निर्माण

» बहुजन निर्बल वर्ग आवास समिति का सच, अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण का आदेश गायब

चेतन गुप्ता

लखनऊ। माइन्स का काम करने वाले वीके सिंह एलडीए अफसरों पर इस कदर भारी है कि उनके अवैध निर्माण की सीलिंग व ध्वस्तीकरण का आदेश न जाने कहां गायब हो गया। निर्माण कार्य चोरी-छिपे बदस्तूर जारी है। यहां बात हो रही है गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 के भूखंड संख्या 1/1335ए की, जिसके मालिक है वीके सिंह। उनके रसूख का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि अफसर चाहकर भी उनके निर्माण पर हाथ नहीं डालना चाहते है। सोसाइटी की जमीनों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे है लेकिन जिम्मेदार कानों में तेल डाले सो रहे है।

शिकायतें मिलने पर अफसर कागजी खानापूरी कर इतिश्री कर लेते है। ऐसा ही कुछ चल रहा है गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-1 में बहुजन निर्बल वर्ग आवास समिति की जमीनों में। अवैध निर्माणों को लेकर जमकर खेल हो रहा है। सरकारी विभाग कठपुतली की तरह नाच रहे है और जेई-सुपरवाइजर हर महीनें लाखों रूपए के वारे न्यारे कर रहे है। जिला प्रशासन ने बहुजन निर्बल वर्ग आवास समिति की बेशकीमती 35 बीघा जमीन अधिग्रहित की जिसको लेकर समिति ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा जीता। अर्जित की गई जमीन में 21 बीघा जमीन समिति को दिए जाने का आदेश हुआ। जिसमें ग्वारी चौराहे से पुल से उतरते ही गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1 में 4 लाख 80 हजार स्क्वायर फुट और सेक्टर 5 में एक लाख बीस हजार स्क्वायर फुट जमीन एलडीए से समिति को 2014 में मिली। इस जमीन पर समिति ने सदस्यों को प्लॉट आवंटित कर दिए। लेकिन लेआउट प्लॉन पास न होने से सभी प्लॉट मालिक फंसे नजर आ रहे है। ले आउट का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। समिति के सदस्यों का कहना है कि न्यायालय की अवमानना के मामले में एलडीए तलब किया गया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि समिति की जमीन का जल्द ही ले आउट प्लॉन पास होगा। लेकिन तब तक कोई निर्माण यदि होता है तो वो अवैध माना जाएगा। सेक्टर -1 में मिली कुल 56,360 वर्ग मीटर जमीन फिलहाल विवादों में है। बिना लेआउट प्लॉन पास कई प्लॉट मालिकों ने चोरी छिपे या एलडीए इंजीनियरों से मिलीभगत करके अवैध निर्माण करा लिया जिस पर उन्हें नोटिस जारी किया गया।

जल्द ही ले आउट प्लान पास हो जाएगा

समिति के सदस्यों की माने तो 6.64 करोड़ रूपए विकास शुल्क के नाम पर जमा कर दिया गया है। हाईकोर्ट में एलडीए के खिलाफ अवमानना का वाद दाखिल है। जल्द ही ले आउट प्लॉन पास हो जाएगा। वीके सिंह का कहना है कि उनकी फाइल शमन के लिए एलडीए में जमा है जहां परिवर्तित नक्शा दाखिल किया गया है। उनके निर्माण की सील खोल दी गई है। सवाल ये उठता है कि जब नक्शा ही नहीं स्वीकृत है तो सील कैसे खुल सकती है। सीलिंग से लेकर ध्वस्तीकरण के मुद्दे पर एलडीए के जेई से लेकर अफसर तक इस प्रकरण पर खुलकर नहीं बोलते है। सबके सब सिर्फ एक ही रटा-रटाया जवाब देते है कि ये जमीन अर्जन से जुड़ी है। इसका मामला हाईकोर्ट के साथ ही शासन स्तर पर लंबित है।

“ वो जमीन अर्जन से जुड़ी है। उसकी फाइल अर्जन विभाग ही देखेगा। बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण नहीं हो सकता। उस समिति का लेआउट प्लॉन पास नहीं है। मौके पर जाकर देखूंगा कि निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसे तत्काल बंद कराउंगा।

सुभाष शर्मा, जेई, प्रवर्तन विभाग, एलडीए

“ अर्जन से जुड़ी जमीन है। न्यायालय और शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है। इसके लिए शासन स्तर एक कमेटी भी बनाई गई है जो जांच-पड़ताल कर रही है। अभी उस जमीन पर किसी का भी नक्शा पास नहीं है। वीके सिंह के संबंध में शिकायत आने पर दो बार उनका निर्माण कार्य बंद कराया जा चुका है।

अरूण कुमार सिंह, ओएसडी, जोन-1

2019 में एलडीए ने नोटिस जारी कर रुकवाया था काम

ग्वारी चौराहे से पुल उतरते ही बाएं हाथ पर 18 हजार वर्ग फुट का वीके सिंह का प्लॉट है जिस पर फार्म हाउस बना हुआ है। वीके सिंह की माने तो ये फार्महाउस चार लोगों के प्लॉट को मिलाकर बना है। माइन्स का काम करने वाले वीके सिंह, उनकी बेटी, अरविंद सिंह व एक अन्य के नाम अलग अलग रजिस्ट्रियां है। 2019 में इस प्लॉट में अवैध निर्माण करने पर एलडीए ने नोटिस जारी कर उसे सील कर दिया गया था लेकिन निर्माण चोरी-छिपे होता रहा। लगातार शिकायतें मिलने पर वीके सिंह समेत 4-5 अन्य प्लॉट मालिकों के अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी जारी हो गए। वीके सिंह ने इसके खिलाफ कमिश्नर के न्यायालय में अपील की और स्टे ले लिया। इसके बाद चोरी छिपे इस निर्माण को पूरा कर लिया गया और उनकी फाइल एलडीए में जानबूझकर दबा दी गई। वीके सिंह लगातार रूक-रूककर निर्माण कार्य करा रहे है। शिकायत मिलने पर एलडीए सुपरवाइजर व जेई दिखावे के लिए काम बंद करा देते है। 2020 में बाउंड्री वॉल खड़ी कर उसे पेंट कराकर फार्म हाउस की शक्ल दे दिया गया।

वाराणसी पहुंचे भूपेंद्र, कॉरिडोर में किया भ्रमण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वाराणसी दौरे पर हैं। भूपेंद्र चौधरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। साथ ही कॉरिडोर में भी भ्रमण किया। प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है।

भूपेंद्र चौधरी सुबह रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। काशी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पवर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में मिशन 80 को पूरा करने के लिए भाजपा ने प्रदेश सरकार के पंचायतीराज मंत्री और पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया।

अब्बास ने हाईकोर्ट से लगाई गुहार, आरोप पत्र रद किया जाए

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने एक बार फिर हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। इस पर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर मामले में दाखिल आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में अब्बास को अंतरिम राहत देते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने अब मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अब्बास अंसारी ने आरोप पत्र को रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल की है। मामला सूचीबद्ध होकर कोर्ट में पेश होगा। अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब-किताब करने की बात कही थी। जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। मामले में अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और वह आगे की कार्रवाई कर रही है।

यूपी में निकाय चुनाव लड़ेगी प्रसपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा। पहले सपा को खून पसीने से सींच कर बड़ा किया, अब प्रसपा को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करना है। गुजरात विधानसभा के साथ-साथ यूपी में भी निकाय चुनाव में प्रसपा उम्मीदवार लड़ाएंगे। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में 403 के मुकाबले प्रसपा के 100 उम्मीदवार उतारने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया था, इसी से सपा की करारी हार हुई। प्रसपा (लोहिया) के प्रदेश मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की सभी सीटों पर उनकी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरेगा।

योगी के राडार पर 73 लापरवाह अफसर

» जनसमस्याओं की अनदेखी करने वाले अफसरों को नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में योगी सरकार ने जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करने पर अफसरों पर कड़ा रुख आख्तियार किया है। इन लापरवाह अफसरों की वजह से जनता के बीच सरकार की छवि धूमिल हो सकती है। चुनाव 2024 नजदीक है। इसी के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनता की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहने वाले 73 अफसरों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है।

स्थानीय प्रशासन, पुलिस आदि द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट, जन सुनवाई पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं। जिन अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें 10 विभागाध्यक्ष, 5 आयुक्त, 10 जिला मजिस्ट्रेट, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त और 10 तहसीलदार शामिल हैं। साथ ही 3 एडीजी, और आईजी, 5 आईजी और डीआईजी, 10 कमिश्नरेट, एसएसपी एसपी के साथ ही 10 पुलिस थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जन शिकायतों और मुद्दों को संबोधित करने के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों की पहचान कर्मियों, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कृषि विपणन, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास, आवास और शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के रूप में की गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य के 73 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस जुलाई महीने की एक रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी विभागों, प्रशासन और पुलिस के साथ कई बैठकें की हैं, जिसमें सभी अवसरों पर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **स्थानीय संपादक** - सूर्यकांत त्रिपाठी*, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।